

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 04 अगस्त, 2008

विषय:- दिया शिक्षा एवं विकास समिति देहरादून को स्टेट ऑफ आर्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु 7.0650 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

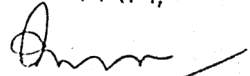
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 443/ डी0एल0आर0सी0-08 दिनांक 3-7-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दिया शिक्षा एवं विकास समिति देहरादून को स्टेट ऑफ आर्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग-1 (उ0प्र0 शासन) के शासनादेश संख्या- 558/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12-9-97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम सेन्टल होप टाउन के खसरा-रां0 1353 गध्ये रकबा 7.0650 है0 भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना दर से निकाले गये नज़राने तथा मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्राण्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

.....(2)

- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।
- (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा संस्था का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं० 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने अथवा ऐसे अन्य कारणों से, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझती है, प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


भवदीय,


(एन०एस० नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
 - ✓ 4- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
 - 5- श्री योगेश आत्रे, सचिव, दिया शिक्षा एवं विकास समिति, 103, खेडा-खुर्द, नई दिल्ली-110082।
 - 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सतोष वडोनी)
अनुसचिव।